Association in Textile and Readymade Garments with USA

2409. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the details of nature of our association with the USA in areas of textiles/readymade garments;

(b) the manner in which these will be affected because of the recent sanctions being imposed by the USA; and

(c) the steps being taken by the Government to surmount these difficulties which textile sector may face in the near future?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) India's exports of textile and readymade garments to the USA had been governed by Bilateral Textiles Agreement under the Multi-Fibre Arrangement till 31st December, 1994. Consequent upon the World Trade Organisation (WTO) coming into force w.e.f. 1.1.1995, the quantitative restrictions (import quotas) in the bilateral agreement under MFA arc being governed by the Agreement on Textiles and Clothing contained in the Final Act of Uruguay Round Negotiations of GATT.

(b) and (c) No sanctions have been imposed by the U.S.A. on export of Indian textiles and apparels" to USA.

राष्ट्रीय वस्त्र मिलों में घाटा

2410. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :
श्रीमती शबाना आजमी :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित बहुत-सी मिलें घाटे में चल रही हैं और कई अन्य मिलें पिछले कई सालों से बंद पडी हुई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा संचालित मिलों की कुल संख्या, घाटे में चल रही मिलों की संख्या और बंद पडी मिलों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) क्या सरकार ने घाटे में चल रही अथवा बंद पडी हुई कपड़ा मिलों को पुनः चलाने तथा उन्हें लाभकारी बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है; यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) और (ख) यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन बहुत सी मिलों में पिछले कुछ वर्षो से घाटे हो रहे है । उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन 119 मिलों में 115 मिलों में 1997-98 के दौरान घाटे हुए । राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन कोई भी मिल बंद पडी हुई नही है क्योंकि वेतन और मजदूरियों का भुगतान किया जा रहा है । तथापि, अज्जूधिया टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को स्थानांतरित करने/नये स्थान पर स्थापित करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 1997 में बंद कर दिया गया था ।

(ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा किये गये एकक-वार अर्थक्षमता अध्ययन के आधार पर सरकार एन0टी0सी0 की अर्थक्षम मिलों के लिए एक संशोधित सर्वागीण सुधार नीति पर विचार कर रही है । जिसके लिए बी0आई0एफ0आर0 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर इन मिलों को निबल पूंजी के सकारात्मक बन जाने के बी0आई0एफ0आर0 के मानदण्ड को ध्यान में रखा जा रहा है । पुनरुद्धार योजना में कामगारों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा ।

हस्तशिल्प दस्तकारों की दयनीय स्थिति

2411. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में हस्तशिल्प दस्तकारों की दयनीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उनकी दशा सुधारने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है या बनाये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में भारतीय संस्कृति से सम्बन्धित हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने हेतु हस्तशिल्प दस्तकारों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है; और

(ड) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान इससे कितने लोग लाभान्वित हुए?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ कारीगरों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कारीगरों की गणना का कार्य फिलहाल चल रहा है । कारीगरों को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने की सुविधाएं देने के लिए सरकार कोई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है । इन योजनाओं में प्रशिक्षण डिजाइन और तकनीकी विकास, विपणन एवं विपणन विकास सहायता, प्रदर्शनी एवं प्रचार, शिल्प विकास केन्द्रों/सामान्य सुविधा केन्द्रों, एम्पोरियमों की स्थापना, पेंशन, वर्कशेड-कम-हाऊसिंग, सामूहिक बीमा और अस्पताल में भर्ती करना शामिल है ।

(घ) और (ड) जी नही । तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) हस्तशिल्प कारीगरों को रियायती ऋण उपलब्ध करा रहे हैं ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

2412. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी** :

श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से राष्ट्रीय वस्त्र निगम के गुजरात और महाराष्ट्र समेत राज्य-वार कुल कितने कर्मचारी लाभन्वित हुये और उनको कितना लाभ पहुंचा है ;

(ख) उक्त कर्मचारियों को श्रेणी –वार कुल कितना वित्तीय लाभ पहुंचा है; और

(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है जिनको उक्त आयोग की सिफारिशों से अभी तक लाभ नही मिला है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम में अध्यक्षों की नियुक्ति

2413. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी** :

श्री दिलीप सिंह जूदेव :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम में सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अध्यक्षों की राज्य-वार संख्या कितनी है और उनके कार्यकाल की अवधि कितनी निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को उनके खिलाफ कदाचार, भ्रष्टाचार और वित्तीय घपलों की शिकायतें मिली है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सतर्कता विभाग ने इस संबंध में कोई विस्तृत जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशी राम राणा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की एक धारक कंपनी है जो नई दिल्ली में स्थित है तथा 9 सहायक निगम अर्थात एन0टी0सी0 (ए0बी0के0के0 एंड एम0) लि0 बंगलौर, एन0टी0सी0 (डी0पी0आर0) लि0, नई दिल्ली, एन0टी0सी0 (गुजरात) लि0, अहमदाबाद में, एन0टी0सी0 (एम0पी0) लि0, इंदौर में, एन0टी0सी0 (एम0एन0) लि0, मुंबई में, एन0टी0सी0 (एस0एम0) लि0, मुंबई में, एन0टी0सी) (बी0 एंड पी0) लि0, कोयम्बटी में, एन0टी0सी0 (यू0पी0) लि0, कानपुर में, एन0टी0सी0 (डब्ल्यू0बी0ए0एंड बी0ओ0) लि0, कलकत्ता में स्थित है । पिछले तीन वर्षो के दौरान अध्यक्ष-सह-प्रबंध निर्देशकों की नियुक्ति एन0टी0सी0 (धारक कंपनी), एन0टी0सी0 (ए0पी0के0के0 एंड एम0) लि0, एन0टी0सी0 (एम0एन0) लि0, एन0टी0सी0 (एस0एम) लि0, एन0टी0सी0 (एम0पी0) लि0, एन0टी0सी0 (डी0पी0 एंड आर0) लि0 तथा एन0टी0सी0 (डब्ल्यू0बी0ए0बी0 एंड ओ0) लि0 तथा एन0टी0सी0 (डब्ल्यू0बी0ए0बी0 एंड ओ0) लि0, में की गयी है । उनकी नियुक्ति 5 वर्षो की अवधि के लिए अथवा सेवा निवृत्ति की तारीख तक/अगले आदेश होने तक, इसमें जो भी पहले हो के लिए की गई थी ।

(ख) और (ग) कुछ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध समय-समय पर मकानों के निर्माण की प्रकृति, बिक्रियों में कमीशन लेने, वित्तीय हेराफेरी करने, कोयले की खरीदारी के सौदों में आपसी लाभ प्राप्त करने, निजी प्रयोग के लिए कारों का इस्तेमाल करने, पदोन्तियों, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा जोब कार्य में अनियमितताएं बरतने झूठे बिलों के दावे करने आदि के बारे में इनकी विस्तृत जांच की गयी ।

(घ) इस संबंध में की गयी जांच के आधार पर उनमें से किसी को भी सिद्ध नही किया जा सका है ।